भारतीय जनसंचार संस्थान

परिचय

भारत सरकार ने १९६२-६३ में फोर्ड फाउंडेशन/यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों के दल से सलाह मांगी। इस द ल ने जनसंचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण शिक्षण और अन संधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की सि ारिश की।

शुरुआत

अगस्त १९६५ को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तत्कालीन प्रभारी इंदिरा गांधी ने संस्थान का औपचारिक उद्घाटन किया।

जनसंचार माध्यम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम संचार के क्षेत्र में आई क्रांति के गवाह हैं। संचार तकनीकों के एकीकरण और उनके समन्वय के कारण नयी चुनौतियों से निपटने और मीडिया, उसकी पहुंच और उसके प्रभाव को समझने के लिए प्रशिक्षण की मांग कई गुना बढ गयी है। पिछले दशकों में भारतीय जनसंचार संस्थान ने जनसंचार शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपनी एक विशेष जगह बना ली है। यह राष्ट्र के विकास और प्रगति में संचार संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और कुशल कर्मियों की नयी चुनौतियों से निबटने के उद्देश्य से उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है।

भारतीय जनसंचार संस्थान को संचार शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में और युवा संचारकर्मियों को प्रिंट पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविजन पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, विकास संबंधी संचार, संचार शोध विज्ञापन एवं जनसंपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करने और तकनीकों से अवगत कराने के लिए पिछले तीस वर्षों में विश्व भर से और यूनेस्को से मान्यता मिली है।

इस संस्थान की स्थापना देश के सर्वांगीण विकास में संचार संसाधनों के उचित और प्रभावी उपयोग के लिए तौर तरीका और तंत्र विकसित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए की गयी थी। इस संस्थान का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त जनसंचार विशेषज्ञों के दल, यूनेस्को के प्रतिनिधियों और देश की मीडिया के जाने माने लोगों ने मिलकर तैयार किया था। इस दल के प्रमुख संचार क्षेत्र की जानी मानी हस्ती डॉ० विल्बर श्रैम थे। इन्होंन अपनी सिफारिश में कहाः

‘जनसंचार के क्षेत्र में उच्चतर अध्ययन का एक केन्द्र ....जिसके पास सलाह, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास की जिम्मेवारी हो, खासकर देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में जनसंचार के उपयोग के संबंध में।’

भारतीय जनसंचार संस्थान १७ अगस्त १९६५ को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक विभाग के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय इसके कर्मचारियों की संख्या बहुत कम थी जिनमें यूनेस्को के दो सलाहकार भी शामिल थे। बाद में २२ जनवरी १९६६ को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ‘१८६०’ के तहत इसका पंजीकरण हुआ।

संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख इसकी प्रस्तावना में किया गया है, जो इस प्रकार है:

- जनसंचार माध्यमों के उपयोग और उसके विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान का आयोजन विशेषकर देश के सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरत को ध्यान में रखते हुए।

- केन्द्र और राज्य सरकारों के सूचना एवं प्रचार विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना ; निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की सचना एवं प्रचार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधायें जुटाना

- जनसंचार सूचना एवं प्रचार से जुड़ी समस्याओं पर विश्वविद्यालयों, शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के साथ साथ व्यवसाय और उद्योग के सहयोग से गोष्ठी, व्याख्यान और संगोष्ठी का आयोजन करना

- रिफ्रेशर कोर्स, समर स्कूल आदि आयोजित करना और देश-विदेश के जनसंचार विशेषज्ञों और शोधार्थियों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करना।

इन दिशानिर्देशों के आलोक में संस्थान प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, अनुसंधान के लिए एक ढांचा तैयार करता है और सूचना का आधारभूत ढांचा तैयार करने में मदद करता है, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि सभी विकासशील देशों के लिए उपयोगी हो। यह अपनी विशेषज्ञता और सलाहकार सेवाएं देश के अन्य संस्थानों को उपलब्ध कराता है, दूसरे देशों के संस्थानों के साथ तालमेल करता है।